वर्ष 3 अंक 11 नवंबर 1981 50 पैसे

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

समाजवादी दुनिया के खिलाफ साम्राज्यवादी साजिशों को नाकाम करो

इस साल 7 नवंबर का ऐतिहासिक दिन हथियारों की झनझनाहट और न्यूक्लीयर युद्ध की तैयारियों के बीच आ रहा है. युद्ध शक्ति में सोवियत संघ व समाजवादी खेमे पर श्रेष्ठता हासिल करने के लिए इस साल की साम्राज्यवादी भाषा है न्यूट्रान बम, परशिंग व क्रुइज मिसाइल और अरबों डालर.

मानव स्वतंत्रता व विश्व शांति के कट्टर दुश्मन अमरीकी साम्राज्यवादी विश्व को न्यूक्लीयर नरसंहार, जिससे लाखों जीवन नष्ट होंगे, के कगार पर ला रहे हैं.

तनाव-शैथिल्य की बात हवा में उड़ गई है. जिनका यह विश्वास था कि साम्राज्यवादी पद्धति को बरकरार रखते हुए तनाव शैथिल्य को स्थायी रूप दिया जा सकता है साम्राज्यवादी नर-भक्षी लक्षणों व चरित्र को भूल गए थे.

तनाव शैथिल्य, हेल्सिंकी घोषणा, साल्ट-II समझौते की मीठी-मीठी बातों से अचानक दूर हो जाना अमरीका में केवल प्रशासन में बदलाव के कारण नहीं है. अमरीकी साम्राज्यवाद का, जो अब चहुमुखी चुनौतियों और अपने हाथ से विश्व के निकल जाने के लक्षणों का सामना कर रहा है, यही वास्तविक चेहरा है.

इसीलिए सीमित न्यूक्लीयर युद्ध की युद्धप्रिय व पाखंडी भाषा है.

युद्ध की कोशिशें किसके खिलाफ हैं ? रीगन ने यह साफ जाहिर कर दिया है कि ये समाजवाद के खिलाफ है. वह आगामी वर्षों में समाजवाद के सूर्यास्त की बात करता है. और वह इसकी तैयारियां न्यूट्रान बमों व नए मिसाइलों से कर रहा है. खोए हुए विश्व को पूंजीवाद के लिए पुनः पाने के लिए अमरीकी साम्राज्यवादी समाजवादी दुनिया के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारियां कर रहा है. रीगन हिटलर के कदमों पर चल रहा है. उसकी इन तैयारियों में ब्रिटेन जैसी कुछ शक्तियां उसका खुल्लम-खुल्ला समर्थन कर रही हैं, हालांकि कुछ दूसरों के दिमाग में गलतफहमियां हैं. लेकिन युद्ध का खतरा वास्तविक है और मजदूर वर्ग को इसका मुकाबला करना है. इरादा यह है कि दुनिया को खून के समुद्र में डुबो दिया जाए, अब तक अनसुना विनाश कर दिया जाए और लाखों लोगों का नरसंहार कर दिया जाए. क्या पाने के लिए ? समाजवाद का सूर्यास्त करने के लिए, अमरीकी सार्वभौमिक इरादे—विश्व पर प्रभुता कायम करने व इसे वशीभूत करने के इरादे—को पूरा करने के लिए.

मजदूर वर्ग अमरीकी बंदूकधारियों के सामने समाजवादी क्रांतियों की विजयों को समर्पित नहीं कर सकता. अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन हिटलर के खिलाफ एकजुट होकर लड़ा और सफलता मिली.

बी टी रणदिवे

आज भी समाजवादी दुनिया की रक्षा के लिए वही आह्वान 7 नवंबर को समूचे देश में अवश्य गूंजना चाहिए. भारत का न तो मजदूर वर्ग ही और न ही समूची जनता इस खतरे की गंभीरता का अहसास करती है, इसका अहसास तो और भी कम है कि युद्ध प्रतिक्रांति इरादे—समाजवाद का सूर्यास्त—के लिए आयोजित किया जा रहा है.

युद्ध का विरोध करने, समाजवादी खेमे के खिलाफ साम्राज्यवादी साजिशों को नाकाम करने के लिए मजदूर वर्ग और जनता को लामबंद करना ही आज सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद का प्राथमिक काम है और भारत का मजदूर वर्ग इस काम को पूरा करने में अपूर्ण नहीं पाया जाना चाहिए.

और भी जरूरी यह इसलिए भी है क्योंकि शासक पार्टी और विपक्षी बुर्जुवा पार्टियां इन सालों में साम्राज्यवाद तथा

२३ नवंबर — दिल्ली चलो

इसकी युद्ध योजनाओं से वास्तविक खतरे को छिपाने में एकबद्ध रही हैं. शासक पार्टी द्वारा दो महाशक्तियों की अविरल चर्चा — जो साम्राज्यवादा व समाजवादी प्रणालियों में फर्क को खत्म कर देती है—अमरीकी साम्राज्यवादियों की आपराधिक साजिशों को गुप्त रखती है. विपक्षी बुर्जुवा पार्टियां आमतौर पर इसी लाइन का अनुसरण करती हैं. और बी जे पी—आर एस एस का राजनीतिक साइनबोर्ड—अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के मामलों में सोवियत व समाजवादी खेमे पर आग बरसाती है और अमरीकी साम्राज्यवाद को साफ छोड़ जाती है. पिछले तीन दशकों में एक के बाद दूसरी कांग्रेस सरकारें दोनों खेमों के बीच नाच करती रहीं, उन्होंने सोवियत सघ से बहुमूल्य सहायता ली, सर्व-महत्व-शाली मित्रता की इंडो-सोवियत संधि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन जनता को यह बताने से इंकार कर दिया कि देश की स्वतंत्रता और विश्वशांति को केवल एक ही स्रोत—अमरीका के नेतृत्व में साम्राज्यवादी खेमे—से खतरा है.

इसलिए लगता है कि देश बेखबर गिरफ्त में आ जाएगा अगर मजदूर वर्ग व ट्रेड यूनियन आंदोलन अपने इस काम को पूरा नहीं करता और जनता को यह नहीं बताता कि युद्ध की अमरीकी तैयारियां तीसरी दुनिया को वशीभूत करने के लिए भी हैं. विश्व को अपनी जरूरत के मुताबिक ढाल लेने की साम्राज्य-वादी योजनाओं का वे हिस्सा हैं. अफगानिस्तान व ईरान में इसकी नीतियों की नाकामयाबी के बाद इसकी जरूरत और भी भारी हो गयी हैं.

सार्वभौमिक प्रभुता की अपनी नीति के तहत अमरीका भारत को इसकी स्वतंत्रता पर हमले तथा युद्ध की धमकी दे रहा है. पाकिस्तान को बेचैनी के साथ हथियारबंद करना, न्यू-क्लीयर हथियारों के विकास की इसकी योजनाओं में भागीदारी, एशियन एशियनों के साथ लड़ें की पुरानी योजना के ही हिस्से हैं. फौरी तौर पर इसका अर्थ है भारत पर दबाव डालने की कोशिशें ताकि भारत मित्रता की इंडो-सोवियत संधि को शिथिल करे या तोड़ दे और अमरीकी अखाड़े में शामिल हो जाए.

भारत के हित प्रत्यक्ष रूप में इसमें हैं कि यह युद्ध का विरोध करे और शांति को बढ़ावा दे.

अमरीका की युद्ध की योजनाएं सीधे-सीधे लाखों लोगों की सुरक्षा पर प्रभाव डालता हैं. समूची दुनिया में शांति के समर्थन में और अमरीका के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं. यह बृहत्तर शांति आंदोलन, जिसमें हर तबके के लोग भाग ले रहे हैं, शांति बनाए रखने तथा जंगबाजों को शिकस्त देने के लिए सर्वहारा संघर्ष को महत्वपूर्ण समर्थन हैं. यह जंगबाजों के अलगाव को दर्शाता है और यह आश्वासन देता है कि जनता उनकी योज-नाओं को शिकस्त दे सकती है और विश्व को न्यूक्लीयर विनाश व नरसंहार से बचा सकती है.

मजदूर वर्ग और हमारी जनता हमलावर युद्ध की तैयारियों के तथ्य को नहीं जानती है.

यूरोप में परशिंग व क्रुइज मिसाइलों को स्थापित करने का प्रस्ताव सोवियत संघ को सीधी धमकी है. इन मिसाइलों से, जो 1,000 से 2,000 किलोमीटर तक वार कर सकते हैं, हिटलर की हार के बाद जमन भूमि से सोवियत संघ के यूरोपीय हिस्से पर हमले का सीधा खतरा है.

अमरीका का डिफेंस बजट 1976 में 100 अरब डालर से भी ज्यादा था, 1980 तक यह 145 अरब डालर तक पहुंच गया. कार्टर द्वारा 1982 में इसे 200 अरब डालर तय किया गया और रीगन द्वारा इसे 227 अरब डालर कर दिया गया. और यह 1986 तक 400 अरब डालर हो जाएगा.

पेंटागन के पास 1980 तक 26 देशों में 20,000 बेस थे जिनका संचालन 2,60,000 अफसर व कर्मचारी करते थे. हिंद-महासागर में अमरीका की बढ़ती उपस्थिति और परशियन गल्फ क्षेत्र में प्रभुता की कोशिशों से इन क्षेत्रों के देशों में पहले ही भारी प्रतिरोध हो चुके हैं.

नाटो के कार्यक्षेत्र के हिस्से के रूप में इन क्षेत्रों को भी शामिल करने की अमरीका आगे योजना बना रहा है.

थैचर का ब्रिटेन अमरीका का इन हमलावर नातियों में समर्थन करता है. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 1980 में अपनी अमरीका यात्रा के दौरान आश्वासन दिया कि "हम ब्रिटेन में आपके साथ हैं. अमरीकी कामयाबियां हमारी कामयाबियां होंगी···आपकी समस्याएं हमारी समस्याएं होंगी. ब्रिटेन में आप पाएंगे एक प्रत्युत्तर, एकसाथी, साहसी, पक्का व सच्चा."

शांति के खिलाफ साजिश की शाखाएं ऐसी हैं.

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की छटपटाती हालत ही इन हमला-वर योजनाओं की जन्मदाता है. साम्राज्यवादी इसलिए समाज-वादी अर्थव्यवस्थाओं की उन्नति को कम करके आंकते हैं, समाजवादी देशों पर कीचड़ उछालते हैं, और प्रतिक्रांति ताकतों का समर्थन करते हैं जैसा कि पोलैंड में हुआ.

लेकिन उनकी अपनी अर्थव्यवस्थाएं अस्तव्यस्त हैं. आज एक बार फिर पूंजीवाद एक दूसरे संकट में है जिसे 1930 के संकट के बाद सबसे गहरा संकट माना जाता है. कई देशों में 1980 में उत्पादन में गिरावट के बाद पूंजीवादी दुनिया 1981 में और अधिक गिरावट का सामना करेगी. पूंजीवादी दुनिया में 1980 के अंत में बेरोजगारी 2 करोड़ 24 लाख थी जिसमें अमरीका का भाग 78 लाख था, एफ आर जी में 13 लाख बेरोजगार थे और फ्रांस में थे 16 लाख बेरोजगार. ब्रिटेन की यह संख्या 1981 के मध्य तक 30 लाख से ज्यादा थी. पूंजीवादी देशों में पिछले दस सालों में कीमतें दुगनी हो गईं और 1975 से इनमें 50 प्रतिशत वृद्धि हुई.

जबकि ज्यादातर पूंजीवादी देशों में वास्तविक वेतन गिरे हैं, 500 सबसे बड़ी अमरीकी कंपनियों के मुनाफों में 1979 तक 23 प्रतिशत वृद्धि हुई और यह 110 अरब डालर था.

इन देशों में अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए शासक औद्योगिक मिलिटरी कंप्लेक्स के कदमों में से एक था अनुत्पादक भारी डिफेंस व्यय. यह नाकामयाब हो गया जिसका परिणाम हुआ छटपटाती स्थिति.

इसीलिए युद्ध के खतरे को गंभीरता से लेना है और इसके खिलाफ दृढ़ता से लड़ना है.

[शेष पृष्ठ तेरह पर]

23 नवंबर के लिए आगे बढ़ो

जिस समय यह अंक पाठकों तक पहुंचेगा उस समय मजदूर वर्ग व मेहनतकश जनता के सभी हिस्से 3 नवम्बर को जोरदार ढंग से प्रतिरोध व मांग दिवस मना कर 23 नवम्बर को संसद के लिये मार्च की पूरी तैयारियां कर चुके होंगे. 'दिल्ली चलो' का नारा फैक्टरियों, दफ्तरों, खेतों व शहरों में गूंज रहा होगा. 4 जून के सम्मेलन द्वारा किए गए पुरजोर आह्वान ने देश के चप्पे-चप्पे में जुझारू ताकतें फैला दी हैं और जम्मू-काश्मीर से अंडेमान निकोबार तक, गोआ से असम तक सभी राज्यों, क्षेत्रों व जिलों के सम्मेलनों के स्थलों को खचाखच भरने के बाद अब यह बोट-क्लब के पार्क को भी पार कर जाएंगी. मजदूर वर्ग व ग्रामीण मेहनतकश जनता की ताकतवर आवाज भारत सरकार को जन विरोधी, मजदूर वर्ग विरोधी, भू-पतिपरस्त, सरमायेदार-परस्त, बहुराष्ट्रीय कम्पनी-परस्त नीतियों को बदलने के लिए एक नोटिस देगी.

मजदूर वर्ग का दृढ़ निश्चय बढ़ रहा है. प्रतिरोध अब संग्राम बन रहा है. केरल, पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा की जनता ने इस कानूनहीन कानून 'एस्मा' को हड़ताली कार्यवाहियों के माध्यम से अस्वीकार कर दिया है. अन्य राज्यों में भी तैयारियां हो रही हैं. वामपंथ नेतृत्व की सरकारों ने यह खुली घोषणा करके कि वे एन एस ए तथा एस्मा का कभी इस्तेमाल नहीं करेंगी जनता व मजदूर वर्ग का नायकत्व किया है. वे वैकल्पिक नीतियां देकर जनवाद के स्तंभ और गरीब जनता के लिए आशा की किरण का काम करती हैं. छटपटाते शासक वर्ग ने, जो बढ़ती मुद्रा स्फीति तथा आसमान छूती कीमतों को रोकने में, जो उनकी पूंजीवादी योजनाओं की देन है, नाकामयाब है, सभी संघर्षों का बर्बरता से दमन करने तथा जनता की आवाज का गला घोंटने का रास्ता अपना लिया है. मजदूर वर्ग ने एकजुट होकर इस चुनौती को स्वीकार किया है. घटी कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की गारंटी के लिये कदमों की मांग उठाकर यह समूची जनता की ओर से बोल रहा है. यह किसानों की ओर से उनके उत्पाद के लिए लाभकारी कीमतों की मांग करके, बोल रहा है. यह मांग कर रहा है बेहतर जीवनयापन के हालात, संगठन की स्वतन्त्रता, सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार और पूरे जनवादी अधिकार. यह एक अधिनायकवादी निजाम की पतनशील नीतियों व दमनकारी कदमों के खिलाफ संघर्ष कर रहा है.

नीचे स्तर से वर्ग एकता स्थापित करने के लिए तैयारियों को कई क्षेत्रों में कार्यरत फूटपरस्त ताकतों का सामना करना पड़ा. उन्हें पृथकतावादी, जातिवादी या धार्मिक मूल्यों पर उठाए गए जनता के आवेश का सामना करना पड़ा. पुलिस के साथ सांठगांठ करके प्रबन्धकों के भाड़े के गुन्डों द्वारा किए गए बर्बर हमलों का उन्हें सामना करना पड़ा. उन्हें सरकार के सभी दमनात्मक कदमों को धराशायी करना पड़ा. कुछ जगहों पर आतंक फैलाने या दूसरे साथियों पर अन्दर से हमला करने की कोशिशों को प्रदर्शनों से या उन्हें नजरअंदाज करके नाकामयाब कर दिया गया. गुस्से से भरी जनता संघर्ष के मुहाने पर है क्योंकि नीतियों में परिवर्तन के लिए संघर्ष के लिए एकजुट होने की फौरी जरूरत के बारे में उनमें चेतना बढ़ रही है. एन एस ए, एस्मा या किसी भी प्रकार का दमन संघर्षों के ज्वार को रोकने में कामयाब नहीं हुआ है. बहुतेरे तो पहले ही संघर्षरत हैं. अनेक ने हड़ताली नोटिस दे दिये हैं. और भी बहुतेरों ने अपनी यह इच्छा जाहिर की है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गयीं तो वे हड़ताल करेंगे.

ये सभी संघर्ष एक जुझारू ताकतवर संग्राम में शामिल हों. 23 नवम्बर का दिन देश के ट्रेड यूनियन आन्दोलन के इतिहास में एक 'स्मरणीय दिवस' बने. मेहनतकश जनता के कदमों की चाप से राजधानी हिल जाए. शासक वर्ग भय से कांपने लगे. तैयारियों में ज्यादा प्रसन्न न हों—अगले कदम के तौर पर एक दिन की हड़ताली कार्यवाही तथा उसके बाद लगातार भरकम कार्यवाहियों की घोषणा के लिए सभी 23 नवंबर के लिए आगे बढ़ें 'दिल्ली चलो' का नारा समूचे देश में गूंजे. वामपंथी जनवादी ताकतें इतिहास द्वारा सौंपी गई महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएं व नेतृत्व हासिल करें. □

राज्य कमेटियां व यूनियनें ध्यान दें

[बी टी आर के 30 सितंबर के सरकुलर नं० 23/81 तथा 2 अक्तूबर के 24/81 के अनुसार]

23 नवंबर को संसद के लिए मार्च

— अपने राज्य से प्रतिनिधियों (पुरूषों व महिलाओं) की संख्या भेजें.

— अपने अनुदान का कोटा भेजें.

— सभी यूनियनें प्रति प्रतिनिधि 3 रुपये इक्ट्ठा करें

— भागीदारी के लिए महिला कामगारों को लामबद करें

नोट- सर्दियां जल्दी शुरू होने के कारण सभी प्रतिनिधि गर्म कपड़े साथ लाए.

नयी दिल्ली में 22 नवंबर को आल इंडिया कनवेंशन आफ वर्किंग वूमैन

राज्यों में सम्मेलन संपन्न

कीमतवृद्धि व सरकार की श्रमविरोधी नीतियों के खिलाफ अब सब राज्यों में संयुक्त सम्मेलन पूरे हो चुके हैं.

कर्नाटक का संयुक्त राज्य सम्मेलन 6 सितंबर को बंगलौर में सीटू, एटक, एच एम एस और यू टी यू सी (एल एस) ने आयोजित किया. इसने सभी मजदूरों का आह्वान किया कि वे 3 नवंबर को प्रतिरोध व मांग दिवस तथा 23 नवंबर को संसद के लिए कूच में भाग लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को लामबंद करें.

बिहार सम्मेलन पटना के श्रीकृष्ण स्मारक हाल में 20 सितंबर को संपन्न हुआ इसे आठ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, सीटू एटक, एच एम एस, यू टी यू सी, बी एम एस, टी यू सी सी, यू टी यू सी, (एल एस) व एच एम पी ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था. केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, केंद्रीय व राज्य सरकार के कर्मचारियों, रेलवे, बैंक, एल आई सी, दवा, कोयला, इस्पात, खदान, विद्युत, डाक-तार, डी वी सी, खेतिहर मजदूर व महिला संगठनों के लगभग 3,000 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया और आह्वान किया कि 3 नवंबर को प्रतिरोध व मांग दिवस प्रदर्शन व रैलियां आयोजित करके मनाएं तथा 23 नवंबर को संसद के लिए मार्च में भाग लें.

जालंधर में 3,000 प्रतिनिधियों से खचाखच भरे देश भगत हाल में पंजाब में मजदूर वर्ग व खेतिहर मजदूरों के नाम 3 और 23 नवंबर के कार्यों का परवाना लिखा गया. यह सम्मेलन सीटू, एटक, एच एम एस व बी एम एस तथा दूसरे जनसंगठनों ने आयोजित किया था. सरकार की श्रमविरोधी नीतियों को चुनौती देने तथा वैकल्पिक आर्थिक नीतियों की मांग करने के लिए सीटू सचिव एम. के. पंधे ने मजदूर वर्ग का जोरदार आह्वान किया कि वे एकजुट हो और 23 नवंबर को संसद पर प्रदर्शन में शामिल हों.

गुजरात में 21 अक्तूबर को अहमदाबाद में संपन्न सर्व यूनियन सम्मेलन ने 3 और 23 नवंबर को आंदोलन की मुख्य धारा में भाग लेने का फैसला किया.

काश्मीर में उरी में 21 व 22 अक्तूबर को संपन्न राज्य सरकार व बैंक कर्मचारियों के एक संयुक्त सम्मेलन ने 3 नवंबर को जोरदार ढंग से मनाने तथा 23 नवंबर के संसद पर प्रदर्शन में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि भेजने का फैसला किया. बंबई सम्मेलन के फैसलों के अनुसार विभिन्न स्थलों पर जैसे शोपियम, त्राल, अनंतनाग, दूरा, पहलगाम, बीजबेहारा, कुलगाम, किलार, अच्छाबल, बांदीपोश, पुलवामा, आदि प्रदर्शन आयोजित किए गए. □

स्वागत समिति बनी

सीटू, डी वाई एफ, एस एफ आई, ए आई डी डब्ल्यू एफ व कई अन्य जन संगठनों की दिल्ली राज्य कमेटियों की एक संयुक्त बैठक में एक 23 सदस्यीय स्वागत समिति का निर्माण हुआ जिसके पी. राममूर्ति, एम. पी., अध्यक्ष तथा सुशील भट्टाचार्य, एम. पी., सचिव हैं. संगठनात्मक कार्यवाही सीटू की दिल्ली राज्य कमेटी के 3, वी. पी. हाउस स्थित कार्यालय से होगी तथा विभिन्न राज्यों व यूनियनों के साथ संपर्क सीटू के 6, तालकटोरा रोड स्थित केंद्रीय कार्यालय से स्थापित होगा.

23 नवंबर को मजदूरों के मार्च संबंधित सभी पत्र विभिन्न राज्यों से इस पते पर भेजें : पी. राममूर्ति, एम. पी, अध्यक्ष, स्वागत समिति, 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-10001. □

एस्मा एक दंड कानून है

लोक सभा में एस्मा पर 15 सितंबर को अभूतपूर्व रिकार्डतोड़ बहस में हस्तक्षेप करते हुए संचारमंत्री सी. एम. स्टीफन ने कहा कि :

"अगर कोई कारण नही होते तो हम इसे नही ला सकते थे. हम सबको ये कारण नही बताते हैं. इसके कारण थे. हमें मालूम था कि रेलवे में क्या हो रहा था, हमें पता था कि डाक-तार में क्या हो रहा था, हमें मालूम था कि विद्युत क्षेत्र में क्या काम हो रहा था. यह अच्छी तरह साफ समझ लिया जाना चाहिए कि हम अंधे नहीं हैं जो अंधेरे कमरे में काम कर रहे हैं. अपनी पूरी तरह खुली आंखों से हम काम कर रहे हैं. हमें मालूम है कि इस देश में क्या हो रहा है···

यह एक संशोधन है जो दंडापराध से निबटने के लिए उठाना होगा. इस कदम से एक नया दंडापराध बताया गया है और यह अदालत द्वारा विचारार्थ अपराध होगा. दंड भी बताया गया है. मुकदमे का तरीका भी बताया गया है. एक दंड कानून लाने में यह पूरी तरह से एक दंड कानून निर्माण है जो आपराधिक कानून के तहत अपराध की परिभाषा देता है और इसका औद्योगिक विवाद कानून से कोई लेना देना नही है..."

कलम के एक वार से औद्योगिक विवादों को अदालत में विचारार्थ अपराध बना दिए गए और भारत के मजदूर वर्ग को सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को इस प्रकार खत्म करके गुलामियत में बांध दिया गया. यदि मजदूर प्रतिरोध करते हैं तो स्टीफन उन्हें दंडित करना चाहता है. □

असम चाए बागान में पुलिस दमन तेज

पुलिस हिरासत में मजदूर की हत्या, नागराजुली व हेरचुरा में गोलीबारी

असम चाए बागान मालिकान ने, खास तौर से कुछ विदेशी कंपनियों ने, इंटक के गुंडों व पुलिस के साथ सांठ-गांठ करके जिसने पुलिस लाक-अप में कैलाश कर्माकार की हत्या कर दी तथा दो को गोली से मार दिया व अनेक घायल कर दिए, एक बार फिर मजदूरों में आतंकराज फैला दिया है. कृष्णकली व चापर चाए एस्टेटों में बर्बर हमलों, बलात्कार व आगजनी के बाद, केंद्रीय शासन के तहत अब पुलिस एक बार फिर हत्या पर्व मना रही है और विदेशी व भारतीय मालिकान के हितों की रक्षा कर रही है.

इस बार संघर्ष बोनस के सवाल पर शुरू हुआ. इंटक से संबंधित असम चा मजदूर संघ (ए सी एम एस) व असम चा कर्मचारी संघ (ए सी के एस) के नेतृत्व ने मालिकान के साथ कोई गुप्त सांठगांठ करके एक सितंबर को एक पर्चा निकाला जिसमें मजदूरों पर दबाव डाला गया था कि वे प्रबंधकों द्वारा प्रस्तावित बोनस (8.33 प्रतिशत) चाहे वह कितना ही हो, को स्वीकार करें तथा यदि कोई विवाद हो तो वह इसके पास भेजें. सीटू से संबद्ध अखिल भारतीय चा मजदूर संघ (ए बी सी एम एस), असम, ने 3 सितंबर को एक पर्चा निकाला और मजदूरों का आह्वान किया कि वे इस साजिश को नाकाम कर दें तथा 20 प्रतिशत बोनस की मांग पर अडिग रहें. ए सी एम एस व ए सी के एस की कई यूनिटों ने अपने नेतृत्व का उल्लंघन करते हुए आम संघर्ष में भाग लिया. एक साजिश की गई व दमन शुरू किया गया. 15 सितंबर को ए बी सी एम एस की टोंगला ब्रांच के सचिव नुरुल अमीन तथा उपाध्यक्ष आफ्ताब हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में रखने के लिए उनके खिलाफ एक के बाद दूसरे आरोप लगाए जा रहे हैं. खारी कतिया चाए एस्टेट के कैलाश कर्माकार को 30 सितंबर को गिरफ्तार किया गया और लाकअप में उसे इतना सताया कि एक अक्तूबर को उसकी वहीं मृत्यु हो गयी. नागराजुली चाए एस्टेटों के मजदूरों पर 10 अक्तूबर का पुलिस ने गोली चलाई जिससे रणजीत ओराओं घायल हुए. कई विधायक व केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि गृह सचिव व मुख्य सलाहकार, असम सरकार, को क्रमशः 12 व 15 अक्तूबर को मिले. हेरचुरा चाए एस्टेट में पुलिस ने 17 अक्तूबर को दो मजदूरों को मार गिराया व अनेक को घायल कर दिया. संघर्ष में सौ से भी ज्यादा मजदूर गिरफ्तार किए गए हैं.

एक प्रैस वक्तव्य में सीटू अध्यक्ष बी टी रणदिवे ने 19 अक्तूबर को पुलिस गोलीबारी व मजदूरों की हत्या की निंदा की है और न्यायिक जांच की मांग की है. सीटू ने ऐसी ही मांगें केंद्रीय गृह मंत्री से भी की है.

सीटू, एटक व अन्य ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप से स्थिति से निबटने का फैसला किया है. असम के राज्यपाल के सलाहकार को एक संयुक्त ज्ञापन में न्यायिक जांच तथा सभी मजदूरों को बिना शर्त रिहा करने की मांग की है. उन्होंने यह भी मांग की है कि मजदूरों की ट्रेड यूनियन गतिविधियों में पुलिस हस्तक्षेप तुरंत बंद किया जाए.

कोकराझार जिला में पुलिस बर्बरता का पिछला हवाला देते हुए, आल इंडिया प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन की शिकायत पर, ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल आफ एग्रीकल्चरल, फोरेस्ट्री एंड प्लांटेशन वर्कर्स ने भारत सरकार को निम्नलिखित निंदा पत्र भेजा है.

"अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों की कनवेंशनों और सिफारिशों के खिलाफ इन कार्यवाहियों की हम कड़ी निंदा करते हैं. इनका अर्थ है मानव अधिकारों के संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन. पांच करोड़ 20 लाख सदस्यों की ओर से ट्रेड यूनियन इंटरनैशनल यह मांग करता है कि दमन को बंद किया जाए, ट्रेड यूनियन व जनवादी अधिकारों तथा स्वतंत्रता को सख्ती के साथ लागू किया जाए और आगे बढ़ाये जाएं तथा आई एल ओ की कनवेंशनों व सिफारिशों को लागू किया जाए व सम्मान किया जाय."

इस विषय पर सीटू ने जनरल काउंसिल की अपनी बेलूर बैठक में एक प्रस्ताव अपनाया है और सरकार को अपना दृष्टिकोण बता दिया है. इसकी शिकायत पर आई एल ओ ने भारत सरकार को पत्र लिखा है.

चहुमुखी प्रदर्शनों व आलोचनाओं के बावजूद दमन का लगातार बढ़ना सरकार के लगातार बढ़ते अधिनायकवादी चरित्र की मोहर है. सीटू तथा आल इंडिया प्लांटेशन वर्कर्स फेड़रेशन बागान मजदूरों के समर्थन में समूचे देश में एकजुटता संघर्षों के लिए काम कर रहे हैं. □

आल इंडिया प्लांटेशन मजदूरों के बैठक

आल इंडिया प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन की वर्किंग कमेटी ने बेलूर (हावड़ा) में 25 अगस्त को संपन्न अपनी बैठक में उद्योग में स्थिति की समीक्षा की. सीटू अध्यक्ष बी टी रणदिवे ने बहस का मार्ग दर्शन किया.

रिपोर्टों से पता चला कि चाए उद्योग में संकट गहराता जा रहा है. जहां चाए का भारी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है वहां मंदी का बोझ महंगाई भत्ते में कटौती करके तथा बोनस न देकर मजदूरों के कंधों पर डाला जा रहा है. बीस से भी ज्यादा बागान बंद है और समूचे देश में बागान मजदूरों पर दमन ढाया जा रहा है जिसने असम में गंभीर शक्ल अपना ली है. बैठक ने सरकार के व बागान मालिकान द्वारा दमन के खिलाफ अखिल भारतीय तथा एकजुटता संघर्षों के बारे में तथा थोक व्यापार व बड़े बागान के राष्ट्रीयकरण की मांग के बारे में विचार-विमर्श किया. □

श्रीमती गांधी के नाम समर मुखर्जी का पत्र

भारतीय रेलवे में सामान्य श्रम संबंध बहाल करो

संसद में सी पी आई (एम) ग्रुप के नेता समर मुखर्जी, एम पी, ने 8 अक्तूबर के अपने पत्र में श्रीमती गांधी का ध्यान ए आई आर एफ के 55 वें वार्षिक सम्मेलन की रिपोर्ट व प्रस्तावों की ओर खींचा है जिसमें रेलवे अधिकारियों पर आरोप लगाया गया है कि वे अनावश्यक "भड़कावे की कार्यवाहियां" कर रहे हैं और "राजनीतिक दबाव या इंटक से सबंद्ध यूनियनों की शह पर भारी मात्रा में विकटमाइजेशन" कर रहे है तथा कहा कि :

"यह खेदजनक हालत हैं. मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार ने 1971 में पारित संस्थानों में मजदूरों के प्रतिनिधित्व संबंधित आई एल ओ कनवेंशन न० 135 अभी तक नहीं अपनाई हैं". उन्होंने आगे कहा :

"ज्यादातर बर्खास्तगियां या जबरन सेवा मुक्तियां स्टाफ को कोई सुनवाई या अपने बचाव का अवसर दिए बिना ही थोप दी गयी हैं. आप इस तथ्य को जानती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 67वें अधिवेशन में भारत सरकार के प्रतिनिधि अपने विचारों के समर्थन में एक भी मत जुटाने में नाकामयाब रहे".

रेल मंत्री के साथ अपने पत्र-व्यवहार का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 'श्री पांडे द्वारा दिए गए सभी तर्क निराधार हैं और उनसे अनुचित श्रम व्यवहार की बू आती है. यदि यह नजरिया जारी रहा तो भारतीय रेलवे में औद्योगिक संबंधों का सामान्य होना दूर की बात ही रहेगी".

रेल मंत्रालय के एड्वाइजर (आइ आर) के 26 नवंबर 1980 के एक गुप्त डी ओ पत्र का हवाला देते हुए जिसमें यह कहा गया है कि "यह साफ साफ समझ लिया जाना चाहिए कि मान्यता प्राप्त यूनियनों के प्रतिनिधियों के अलावा दूसरों की सुनवाई केवल कर्मचारियों का व्यक्तिगत या छोटे दल के रूप में उनकी समस्याओं व कठिनाइयों को सुनने व परीक्षण करने के लिए केवल प्रशासनिक सुनवाई का ही मामला है," समर मुखर्जी ने बाद में एक पत्र में कहा कि यह 27 मई 1978 के एक पहले डी ओ पत्र में लिखी नीति को खत्म करना है हालांकि सरकार ने 1980 में यह घोषणा की थी कि पहले सभी वादों को पूरा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह ए आई एल आर एस ए के महासचिव की इस धारणा को सिद्ध करता है कि उन्हें पहले दिया गया संचार माध्यम नवंबर 1980 से ही खत्म कर दिया गया है. रेल मंत्री का संसद में 17 फरवरी 1981 को अपनी मर्जी से दिया गया बयान नवंबर 1980 में किए गए काम को मात्र औपचारिक रूप देता है.

फिर से 26 नवंबर 1980 के डी ओ पत्र का हवाला देते हुए जिसमें कहा गया है कि 'दूसरी ओर मौजूदा जोर मान्यता प्राप्त यूनियनों की अपने खेमे में पर्याप्त मात्रा में कर्मचारियों को लाने में अपनी भूमिका अदा करने में सहायता करना है" समर मुखर्जी ने कहा कि ए आई आर एफ के मथुरा सम्मेलन में अपनाए गए प्रस्ताव को मध्येनजर रखते हुए यह प्रतीत होता है कि रेलवे प्रशासन कर्मचारियों को एन आई एफ आर में शामिल होने के लिए मजबूर कर रहा है या उन्हें दंडित कर रहा है. उन्होंने इस लिए श्रीमती गांधी से अनुरोध किया कि वह "तुरंत हस्तक्षेप करें और सामान्य संबंधों को बहाल करें." □

रेलवेकर्मी यकायक भड़क उठे

वाल्टेयर डीजल शेड में 21 सितंबर को एक इलैक्ट्रिक फिट्टर की छत से गिरकर मृत्यु होने तथा रेलवे डाक्टर द्वारा ध्यान न देने के कारण गुस्से से भरे मजदूरों ने डाक्टर की लापरवाही के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग करते हुए काम रोक दिया और उन सभी अफसरों को जो शेड में आए घेराव किया. पुलिस सुपरिटेंडेंट के हस्तक्षेप करने पर और उस द्वारा यह अश्वासन दिये जाने पर कि डाक्टर के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी व कोई विक्टिमाइज नही किया जाएगा, मजदूरों ने काम शुरू किया. लेकिन चार दिन बाद तीन मजदूरों को घृणित नियम 14 (ii) के तहत सेवामुक्त कर दिया गया है और एक को गिरफ्तार कर लिया गया है.

बोकारो इस्पात नगर के आपरेटिंग स्टाफ ने आर पी एफ स्टाफ की फुटबाल मैच में हार के बाद गुंड़ागर्दी के खिलाफ प्रतिरोध में पांच घंटे काम बंद कर दिया. इस आश्वासन के बाद कि संबंधित आर पी एफ स्टाफ के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी मजदूरों ने काम शुरू किया. □

सीटू नामांकन

कनाडा की बहुराष्ट्रीय कंपनी अल्कान (ए एल सी ए एन) के मजदूरों को लामबंद करने के लिए कनफेडरेशन डेस सिंडीकेट नेशनाक्स ने 5 से 9 अक्तूबर तक मोनट्रील में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित की. सीटू ने जनरल काउंसिल के सदस्य के बालचंद्रन को इसमें भाग लेने के लए नामजद किया.

सीटू की पंजाब राज्य कमेटी के अध्यक्ष जगजीत सिंह लायलपुरी को सीटू ने सेंट्रल स्टेंडिग कमेटी आन बांडेड, मार्ग्रेट एंड केजुअल लेबर के सदस्य के रूप में नामजद किया है. □

अंडेमान व निकोबार के सरकारी कर्मचारियों द्वारा सांकेतिक हड़ताल का फैसला

ए एडं एन सरकार के कर्मचारियों व मजदूरों की फेडरेशन की फेडरल काउंसिल की 30 सितंबर को हुई बैठक ने यदि आठ सूत्री मांगत्र पर कोई समझौता नहीं हुआ तो 27 नवंबर 1981 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने का आह्वान करने का फैसला लिया.

एक प्रस्ताव में एक बिरादराना संगठन द्वारा आयोजित जुलूस में भाग लेने पर कर्मचारियों को विक्टिमाइज किए जाने तथा फेडरेशन व अन्य ट्रेड यूनियनों द्वारा 6 सितंबर को आयोजित जुलूस में भाग लेने पर कर्मचारियों से जवाब-तलब करने के खिलाफ प्रतिरोध व्यक्त किया गया है. अधिकारियों ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें फेडरेशन द्वारा आयोजित जुलूस में कर्मचारियों द्वारा भाग लेने पर रोक लगा दी गयी थी. इसका मतलब संगठन के अधिकार व संगठन की स्वतंत्रता पर रोक है.

मांग पत्र में मुअत्तिल किए गए पी डब्ल्यू डी के 105 मजदूरों की पुनः बहाली, आकस्मिक व दैनिक वेतन पर काम करने वालों और एन एम आर स्टाफ के लिए सेवा शर्तें, सवेतन साप्ताहिक छुट्टी आदि की मांगें जो मजदूरों के प्राथमिक कानूनी अधिकार हैं, शामिल हैं. □

ए आई आर एफ द्वारा हड़ताल के लिए मतदान का फैसला

हाल ही में मथुरा में संपन्न ए आई-आर एफ के 55 वें जनरल सम्मेलन में अपनाए गए एक प्रस्ताव में कहा गया है कि पिछले वर्ष के बीकानेर सम्मेलन के बाद दायर किए गए 10-सूत्री मांग पत्र पर यदि सरकार कोई समझौता नहीं करती है तो ए आई आर एफ के पास रेलवे कर्मचारियों को फरवरी 1982 में संसद के समक्ष लामबंद करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा और इसने हड़ताल के लिए मतदान का फैसला लिया. एक अन्य प्रस्ताव में महासचिव को कहा गया है कि सरकार से बातचीत के समय तीसरी चौथी जनरेशन के कंप्यूटरों के खिलाफ मांग को भी वे शामिल कर. □

डिफेंस कर्मचारियों ने हड़ताल का निर्णय लिया

जबलपुर में 24 से 28 सितम्बर तक हुए 'आल इंडिया डिफेंस एंप्लाइज फेडरेशन' के चौदहवें सम्मेलन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि 31 दिसम्बर 1981 से पहले 11 अगस्त 1979 को हुए समझौते को पूर्ण रूप से लागू न किया गया तो वे आम हड़ताल करेंगे. फेडरेशन द्वारा पेश किए 9 सूत्रीय मांगपत्र पर समझौता हुआ था जिसे लागू नहीं किया गया है और इसी कारण 18 दिसम्बर 1980 को कर्मचारियों को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने के लिए मजबूर होना पड़ा था. इसके बाद भी इसे केवल आंशिक तौर पर लागू किया गया था. फेडरेशन ने एक प्रस्ताव में कहा है कि कर्मचारियों की अधीरता अब खत्म हो चुकी है और उनके पास आम हड़ताल करने के निर्णय के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा है. □

एन एस ए व एस्मा की परवाह न करते हुए

लेखा कर्मचारियों का हड़ताल का निर्णय

भारतीय आडिट एंव एकाउंट विभाग के कार्यों में राजनीतिक व नौकरशाही हस्तक्षेप ने संविधान की धारा 148 (5) का मजाक बना दिया है.

विभाग के 55,000 कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली 'आल इंडिया नान गजेडिट आडिट एंड एकाडंट एसोसिएशन' की कार्यकारिणी कमेटी की 23-24 सितंबर को नागपुर में मीटिंग हुई जिसमें फरवरी 1982 के दूसरे भाग में एक दिन की हड़ताल करने के लिए दिसम्बर 1981 में हड़ताल के लिए मतदान कराने का निर्णय लिया गया काम की जिम्मेदारियां और सघनता के आधार पर वेतनमान और एक ऐसी व्यवस्था जिसमें स्थिरता न हो, रिक्त स्थानों की पूर्ति जो स्वीकृत संख्या के 25प्रतिशत से भी अधिक है, रिआर्गेनाइजेशन स्कीम को लागू करने में एकतरफा नीति को खत्म करना आदि उनकी मुख्य मांगें हैं. इस विभाग में अनोखी बात यह है कि बुनियादी कार्यरत वर्ग जो कि 'आडिटर' कहलाते हैं और जो शैक्षणिक तौर पर काफी पढ़े-लिखे होते हैं और यू डी सी वेतनमान पा॰ हैं, के लिए पदोन्नति के अवसर नहीं होते और वे अनेक वर्ष नौकरी करने के बाद भी 'आडिटर' के रूप में ही सेवामुक्त हो जाते हैं.

कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में 5 जून को 'अखिल भारतीय विरोध दिवस', 26 जून को एक घंटे के लिए 'विभाग बहिष्कार' कर मांग सप्ताह जुलाई के अंत में 'असहयोग सप्ताह' और 16 से 18 सितंबर तक 'क्रमिक-धरना कार्यक्रम' आयोजित किया. प्रथम श्रेणी के अफसरान को छोड़कर स्टाफ और अफसरान के तीन अखिल भारतीय संगठनों ने एक 'आल इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटी' बनाई जिसने समूचे देश में प्रान्तीय गोष्ठियां करने का और नवंबर के तीसरे सप्ताह में राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन करने का निर्णय लिया. भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा जिसमें विभाग को स्वायत्त बनाए रखने के लिए, भारत के कंपट्रोलर और आडिटर जनरल की नियुक्ति के तरीके, आडिट व एक्जीक्यूटिव के बीच संबंध, आडिट के चरित्र से संबंधित प्रश्न पर एक उच्चस्तरीय कमेटी की मांग की जाएगी.

कर्मचारियों की मांगों के प्रति सरकार के अड़ियल रवैये ने उन्हें आन्दोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर किया है. □

ट्रेड यूनियनों में गांधीवादी सिद्धांतों का अर्थ है

वर्ग सहयोग का सिद्धांत : हड़ताल विरोधी अमानतदारी

—पी. राममूर्ति

[मेरठ कालेज के इतिहास विभाग द्वारा 3-4 अक्तूबर को आयोजित 'गांधीवादी आंदोलनों पर गोष्ठी' में सीटू के महासचिव पी. राममूर्ति ने अध्यक्षीय भाषण दिया. नीचे सूचना के लिए ट्रेड यूनियन आंदोलन के बारे में उनके विचारों के कुछ अंश प्रकाशित किये जा रहे हैं.—सं.]

पी. राममूर्ति ने कहा—

ट्रेड यूनियन आंदोलन में गांधी के सिद्धांतों का सारांश आज अमानतदारी का सिद्धांत माना जाता है. संक्षेप में, यह सिद्धांत ये विचार प्रस्तुत करता है कि संपत्ति के स्वामी, जो श्रम की नियुक्ति करते हैं, उस संपत्ति के अमानतदार (ट्रस्टी) का काम करेंगे, उन्हें ऐसा काम व व्यवहार करना चाहिए कि ट्रस्टी अपनी संपत्ति का प्रबंध समूचे समाज के हित में कर रहा हो. उन्हें स्वार्थ या संपत्ति को बढ़ाने के इरादे से काम नहीं करना चाहिए. उन्हें ऐसी किसी उत्तेजना का शिकार नहीं बनना चाहिए. जाहिर है इसमें आधुनिक उद्योग के स्वामी भी शामिल हैं...

अहमदाबाद में 1918 में मजदूरों ने हड़ताल की थी और मिलों के चक्के जाम हो गये थे. अहमदाबाद के मिल मालिकान के नेता व प्रवक्ता उस समय अहमदाबाद मिल मालिकान एसोसिएशन का अध्यक्ष, अंबाला साराभाई, गांधी का दोस्त था. गांधी उस समय चंपारण में राष्ट्रीय स्कूल का आयोजन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अंबाला साराभाई की बहन अनुसूयाबाई साराभाई का पत्र पाते ही अपना रचनात्मक काम छोड़ दिया तथा हड़ताल में हस्तक्षेप करने के लिए वे तुरंत अहमदाबाद पहुंचे. अहमदाबाद पहुंचने पर उन्होंने पाया कि मिल मजदूरों की मांगें उचित हैं और हड़ताल जायज है. अगस्त 1917 से उन्हें 70 या 80 प्रतिशत बोनस मिल रहा था और उस शहर में प्लेग की बीमारी फैलने के बाद 1918 में मिल मालिकान ने इसे अचानक वापस ले लिया था. मजदूरों ने उस समय कम से कम 50 प्रतिशत की मांग की. यह हड़ताल की बुनियाद थी.

स्थिति के साथ निबटने की स्वयं गांधी ने जो व्याख्या की है वह ट्रस्टीशिप (अमानतदारी) के सिद्धांत की झलक पेश करता है जिसे बाद में उन्होंने विकसित किया और उसे उच्च चरित्र सिद्धांत के रूप में ऊपर उठाया.

अपनी आत्मकथा में गांधी लिखते हैं :

"मैं बहुत ही नाजुक स्थिति में था. मिल मजदूरों का मुद्दा मजबूत था. श्रीमती अनुसूयाबाई को अपने ही भाई श्री अंबाला साराभाई, जो मिल मालिकान की ओर से झगड़े का नेतृत्व कर रहा था, के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा. मेरे उनके *साथ दोस्ताना संबंध थे*, और इसने उसके साथ लड़ाई को और भी कठिन बना दिया. मैंने उनके साथ परामर्श किये कि मामले को पंच-फैसले के लिए सौंप दिया जाए, लेकिन उन्होंने पंच-फैसले के सिद्धांत को मानने से इंकार कर दिया. *इसलिए मुझे मजदूरों को यह सलाह देनी पड़ी कि वे हड़ताल पर जाएं.*"

लेकिन फिर उन्होंने मांग को 35 प्रतिशत तक कम कर दिया और मजदूरों पर अपंग शर्तें थोप दी. उन्हें हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए, उन्हें हड़ताल तोड़ने वालों को तंग नहीं करना चाहिए, उन्हें दया-भिक्षा पर (यानि हड़ताली संघर्ष फंड आदि) निर्भर नहीं करना चाहिए, और वे हड़ताल के दौरान यदि हो सके तो किसी और जगह जाकर काम करें. ये हजारों मजदूर दूसरी जगह कैसे काम पा सकते थे जबकि ग्रामों और शहरों में बेतहाशा बढ़ती बेरोजगारी उसकी चिंता का विषय नहीं था. उनका कहना यही था कि वे इस दौरान भूखों मरें और इस तरह अपने बच्चों व आश्रितों को भी भूखा मारें तथा इस तरह मिल मालिकान की हड़ताल तोड़ने में मदद करें, और, यदि यह संभव नहीं था, तो मालिकान की शर्तों पर हड़ताल को वापिस ले लें. यह उनका महान सिद्धांत था.

गांधी आगे कहते हैं :

"हड़ताल इक्कीस दिन चली. हड़ताल के दौरान समय-समय पर मैंने मिलमालिकान से विचार-विमर्श किया और उनसे मजदूरों के साथ न्याय करने के लिए विनती की. 'हमारा भी संकल्प है', वे कहा करते थे. 'हमारे मजदूरों के साथ संबंध मां-बाप व बच्चों के समान हैं. हम एक तीसरी पार्टी के हस्तक्षेप को कैसे सहन कर सकते हैं'. पंच के फैसले के लिए कहां जगह है ?"

लेकिन गांधी की सभी विनतियों की कोई सुनवाई नहीं हुई. मजदूरों में मिलमालिकान के प्रति घृणा का पनपना स्वाभाविक था और वास्तव में वह बढ़ रही थी. गांधी को डर लगा कि गुंडागर्दी फैल जाएगी. उनके सामने यह भय नाच रहा था कि हड़ताल मजदूरों की भूखों मरने में नाकामयाबी से टूट जाएगी. इसलिए मजदूरों के इस मनमाने नेता व प्रवक्ता को निष्पक्षता के सिद्धांत को तोड़ना पड़ा. जब उनके अपने मित्रों से—मिल-मालिकान—कारण जानने के लिए सभी प्रस्ताव तथा विनतियां असफल हो गईं, उन्होंने घोषणा की कि "जब तक हड़ताली लामबंद नहीं होते हैं और किसी समझौते के होने तक हड़ताल जारी नहीं रहती है या *जब तक वे मिल को पूरी तरह छोड़ नहीं देते हैं, मैं* भोजन नहीं छुऊंगा."

शब्दों को ध्यान से नोट कीजिए. वर्ग शांति, ट्रस्टीशिप, पंच-फैसले की इमारत गिर रही थी. उनका आत्म सम्मान कसौटी पर कसा था. उन्होंने अहसास किया कि बिना किसी दबाव के उसके पूंजीवादी मित्र, अपने दीर्घकालीन हितों को पूरा करने के लिए भी, टस से मस नहीं होंगे. उन्होंने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को नहीं स्वीकारा जिसको बाद में उन्होंने इतना ऊपर उठाया. एक ट्रस्टी या उन जैसे मित्र के हाथ में वे अपने स्वार्थों को सौंपने के लिए सहमत नहीं होंगे.

मुनाफे में उनका लालच जबरदस्त था. लेकिन मिल मालिकान ने उस हालत को पहचाना जिसमें अब उनका मित्र पहुंच गया था और यह भी पहचाना कि अगर गांधी मर गए तो उनके अपने हितों को, फौरी और दीर्घकालीन दोनों, भी क्या खतरा होगा तथा साथ ही अहमदाबाद व समूचे देश में इसके क्या परिणाम होंगे. वे कम से कम माने तो और उन्होंने अपने ही आदमी श्री आनंद शंकर धरुवा को पंच नियुक्त किया. पंच के इस चयन में न तो मजदूरों का ही और न ही गांधी का कोई हाथ था और अंततः उन्हें केवल 27.5 प्रतिशत बोनस पर फैसला करना पड़ा, यह स्वयं गांधी द्वारा सोचे गए जायज व उचित समझौते से काफी कम था.

लेकिन, इसी दौरान गांधी ने मजदूरों की लामबंदी तोड़ने में अपनी पूरी कोशिश की थी. उसने श्रीमती अनुसूयाबाई व साथी मजदूरों को अपने साथ भूख हड़ताल करने से मना कर दिया. यह उनके सत्याग्रह, विरोधी के हृदय परिवर्तन और न जाने क्या-क्या की धारणा थी.

पंच की नियुक्ति के बाद हड़ताल वापिस ले ली गयी जिससे मिल मालिकान को काफी आनंद मिला. इस घटना का आनंद उन्होंने मजदूरों में मिठाई बांट कर लिया. उनके मित्र के हस्तक्षेप से कम से कम वर्ग शांति का आश्वासन तो मिला था. हड़ताल के इस रंगीन अंत पर गांधी की क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने कहा कि मजदूर मिठाई के पीछे हाथ पैर मारने वाले लालची हैं. गरीब मजदूर, जो तीन सप्ताहों से भी ज्यादा के लिए भूख व भुखमरी की दिक्कतों से गुजरे थे, वह भी गांधी के कहने पर, अगर वे मिठाई के लिए हाथ पैर मार रहे थे (मान लीजिए उन्होंने ऐसा किया भी) तो वे लालची हैं!

बेशर्मी के साथ समझौता न करने और मिल मालिकान के लालच के अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस घिनौनी प्रशंसा की. और सबसे ज्यादा श्रद्धा, जिसके कारण वे मजदूरों को इकठ्ठा कर सके, मिल मालिकान के नेता व अपने प्यारे मित्र श्री अंबाला साराभाई के लिए थी: "उसकी दृढ़ इच्छा व साफ ईमानदारी अद्भुत थी और इसने मेरा हृदय मोह लिया. उसके खिलाफ होने में मुझे आनंद मिला. इसलिए मेरे उपवास से विपक्षियों, जिनका कि वह नेता था, पर जो दबाव पड़ा उसने मेरे दिल पर गहरा असर किया और फिर, उसकी पत्नि सरलादेवी का मुझसे सगी बहन की तरह लगाव था, और मैं उसे अपनी कार्यवाही पर पीड़ित नहीं देख सका"...

केवल इस बात पर गौर कीजिए कि उन बहादुर मजदूरों का, जिन्होंने हर कठिनाइयों के बावजूद तीन सप्ताहों से भी ज्यादा हड़ताल की थी, उन्होंने कितना अपमान किया और इस पर गौर कीजिए कि उनकी अपनी आत्मकथा से उद्धृत उपरोक्त पैरे में मालिकान के नेता के लिए उन्होंने क्या सुंदर प्रशंसा की थी, और यहां कोई भी यह समझ सकता है कि मजदूर वर्ग व उनकी संगठित जनकार्यवाहियों के प्रति उनके क्या विचार व दृष्टिकोण थे. जनता के उनकी जनगतिविधियों की सीमा, जिसे उन्होंने तय किया था, से ऊपर उठने का डर उनके समूचे जीवन में उनका पीछा करता रहा.

यह सत्य है कि गांधी ने मजूर महाजन (जो बाद में अहमदाबाद टैक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के नाम से प्रचलित हुआ) संगठित किया. लेकिन, वह इसमें अकेला नहीं था. देश में फैली हड़ताल की लहर का परिणाम था समूचे देश में संगठित ट्रेड यूनियनों का निर्माण. उन्होंने आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के निर्माण की नीव रखी जिसका उद्घाटन और अध्यक्षता लाला लाजपतराए ने की थी. और बाद में 1917 तक राष्ट्रीय आंदोलन के चितरंजन दास व जवाहर लाल नेहरु जैसे नेता इसके अधिवेशनों के अध्यक्ष रहे. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भारतीय ट्रेड यूनियनों का प्रतिनिधि नामजद करने का स्तर एटक को हासिल हुआ.

लेकिन गांधी ने मजूर महाजन को विकासमान मजदूर वर्ग आंदोलन की मुख्य धारा से दूर रखा. क्योंकि अखिल भारतीय संगठन ने उनके ट्रस्टीशिप के सिद्धांत, वर्ग शांति व वर्ग संघर्ष को त्यागने को नहीं स्वीकारा. दूसरी और उनके लिए तो समाजवाद एक अभिशाप था.

यहां यह बता देना कोई गलत नहीं होगा कि जार के रूस के मजदूर वर्ग ने प्रथम विश्व युद्ध के अंत के दिनों में, 1917 में, राजनीतिक शक्ति हासिल कर ली थी, और पहला समाजवादी देश पैदा हुआ था. लेकिन उनके पास उसकी प्रशंसा के लिए कोई भी शब्द नहीं था. दूसरी और तत्कालीन राष्ट्रीय कवियों ने, जैसे तमिलनाडु के अमर कवि सुब्रह्मण्यम भारती, इस क्रांति की नए जमाने का शुरूआत कहकर प्रशंसा की, जैसा कि रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद व अनेक अन्यों ने किया. लेकिन भारत के मजदूर वर्ग ने 1921 में एटक के झारिया अधिवेशन में रूस के, जो आठ हमलावर सेनाओं व गृह युद्ध के शिकंजे से निकला था, अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए एक दिन के वेतन का अनुदान करने के लिए सभी मजदूरों का आह्वान किया. एक बार फिर यहां प्रदर्शित होता है कि मजदूर वर्ग व गांधी के विचारों में कितना फर्क था....

आश्चर्य की बात है कि 1937-38 में जब कानपुर के टैक्सटाइल मिल मजदूरों ने कांग्रेस सरकार पर महान आशाएं रखते हुए आम हड़ताल की थी, गांधी ने मजदूरों द्वारा की गई मास पिकेटिंग की घोर निंदा की थी. उन्होने इसकी हिंसा व दबाव तथा अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ कहकर व्याख्या की और यह भी इसके बावजूद कि हड़ताली मजदूरों ने किसी को छुआ तक नहीं, उन्होंने केवल यही कहा था कि कोई भी फैक्टरी के अन्दर न जाए. मिल मालिकान के भाड़े के गुंडों द्वारा गुंडा हमलों या सरकार द्वारा हड़ताली मजदूरों के खिलाफ क्रिमिनल ला अमेंडमैंट एक्ट, वह कानून जिसे वायसराय द्वारा उस समय खास तौर से लागू किया गया था जब कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं ने कपड़े की विदेशी दुकानों तथा अरक व ताड़ी की दुकानों के खिलाफ नागरिक अवज्ञा आंदोलन के दौरान पिकेटिंग शुरू की थी, इस्तेमाल करने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं थे. गांधीवादी सिद्धांतों के मुताबिक उस पिकेटिंग की श्रेणी भिन्न थी, लेकिन मजदूरों द्वारा पिकेटिंग जबरदस्ती, अहिंसा और न जाने क्या-क्या थी.

हड़ताल के बारे में गांधी ने अपने विचारों को कभी नहीं बदला. अपने अंतिम सार्वजनिक भाषणों में उन्होंने 26 जनवरी 1948 को घोषणा की.

"एक सुगठित जनवादी समाज में कानूनहीनता या हड़तालों के लिए कोई जगह नहीं है. ऐसे समाज में ऐसे बहुतेरे कानून हैं जिनके तहत न्याय की मांग की जा सकती है."

लेकिन उन्होंने स्वयं एक बार पहले यह कहा था कि 'न्याय भी एक तुलनात्मक मद है,' इसकी धारणा न्यायधीश के वर्ग झुकाव पर निर्भर करती है जिसका सबूत हाई कोर्टों व सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णित अनेक मामलों से मिलता है. स्वयं गांधी भी अहमदाबाद में पंच से वह नहीं प्राप्त कर सके जिसे उन्होंने जायज व उचित समझौता माना था. और फिर भी वे कहते हैं कि न्याय पाने के लिए हड़तालों के अलावा और भी कई साधन हैं.

वर्ग झुकाव जाहिर है. अगर हड़ताल के लिए कोई जगह नहीं है तो उनके दिमाग में जाहिराना तौर पर मजदूरों पर जबरन पंच फैसला थोपना है. हड़तालें, जो वर्ग समाज में वर्ग संघर्ष का एक चरण है, उनके लिए अभिशाप हैं. तब तो वर्ग शांति और शोषण प्रणाली को हर हालत में सुरक्षित रखना होगा...

तब, फिर, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या था ? आनाकानी करते हुए उन्होंने मूल्य का श्रम सिद्धांत स्वीकार किया कि भौतिक मूल्य मजदूरों, किसानों, खेतिहर मजदूरों और दस्तकारों के श्रम द्वारा ही पैदा किया जाता है. वे यहां तक कहते हैं कि "श्रम ही पूंजी है." लेकिन समूचे समाज की ओर से इस पूंजी पर मजदूर वर्ग के कब्जे और इसे सामाजिक स्वामित्व में संपत्ति में बदलने से वे परहेज व नफरत करते हैं. वे यह मानते हैं कि एकाध मामले को छोड़कर, जिसमें किसी के हाथ गुप्तधन लग जाता है, धन की बुनियाद शोषण पर ही टिकी है. वे कहते हैं कि "सबको एक ही ब्रश से पोता जाता है" और "न्याय भी एक तुलनात्मक मद है".....

यह साफ जाहिर है कि ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को वर्ग झुकाव से मुक्त किसी कल्पना की देन नहीं कहा जा सकता. इसको इस तरह से पेश करना मजदूर वर्ग व मेहनतकश जनता के साथ छल-कपट करना होगा. इसका इस तरह से साफ समझ लेना चाहिए कि यह पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा के लिए सिद्धांत या मत है और यह समाजवादी क्रांति के ज्वार को रोकने के लिए उनके हाथ में एक हथियार हैं (क्रमशः)···□

ई एस आई सी कर्मचारियों की हड़ताल

यदि अधिकारी कमेटी आफ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रस्तावित बोनस जिसे ई. एस.आई. स्टेंडिंग कमेटी तथा श्रम मंत्रालय ने पारित कर दिया हैं, देने में असफल हुए तो अखिल भारतीय ई. एस. आई. सी एंप्लाईज फेडरेशन 5 नवम्बर को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करेगी.□

महंगाई के आंकड़े

(आधार 1960-100)

राज्य/केंद्र	1981		
	अग.	जून	जुला.
बिहार			
जमशेदपुर	428	415	420
झारिया	420	405	409
कोडर्मा	464	437	450
मोंघाइर	491	456	473
नोआमुंडी	341	419	426
गुजरात			
अहमदाबाद	441	427	438
भाव नगर	465	448	454
हरियाणा			
यमुना नगर	481	468	477
जम्मू व काश्मीर			
श्रीनगर	471	459	465
मध्य प्रदेश			
बालाघाट	467	452	462
भोपाल	477	461	470
ग्वालियर	482	467	481
इंदौर	492	480	487
महाराष्ट्र			
बंबई	462	450	459
नागपुर	466	454	459
शोलापुर	504	482	490
पंजाब			
अमृतसर	473	452	460
राजस्थान			
अजमेर	481	470	477
जयपुर	499	487	491
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	446	429	445
सहारनपुर	450	436	445
वाराणसी	494	484	491
पश्चिम बंगाल			
आसन सोल	449	440	444
कलकत्ता	412	406	408
दार्जीलिंग	365	350	360
हावड़ा	395	390	392
जलपाइगुरी	364	348	357
रानीगंज	422	442	425
दिल्ली	480	461	476
भारत	454	439	447

गुजरात में सीटू के बढ़ते कदम

मजदूरों के आंदोलनों व संगठनों में हाल के विकास गुजरात में सीटू नेतृत्व में बढ़ते विश्वास को दर्शाते हैं. राजधानी अहमदाबाद में सीटू नेतृत्व व सीटू यूनियनों के नेतृत्व में टैक्सटाइल, इंजीनियरिंग, रंग, रसायन, छापाखाना, डेरी, आदि जैसे विभिन्न उद्योगों में लगातार आंदोलनों का मुख्य केंद्र रहा.

टैक्सटाइल : अरविंद टैक्सटाइल मिल के प्रबंधकों ने सीटू नेता सरूरुद्दीन चाचा को इस झूठे आरोप पर सेवामुक्त कर दिया था कि चाचा 20 साल पहले एक साथ दो मिलों में काम करता था. मजदूरों द्वारा भारी आंदोलन शुरू किया गया. कांग्रेस (आई) सरकार ने, अपने वर्ग चरित्र के अनुसार, तुरंत धारा 144 लगादी और 17 मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया. लेकिन मजदूरों ने शिकस्त मानने से इंकार कर दिया और धारा 144 तोड़ कर जवाब दिया. टैक्सटाइल सरमायेदार कस्तूरभाई के सभी सातों मिलों में गेट मीटिंगें व आंदोलन हो रहे हैं. पुलिस को गिरफ्तार किए गए सभी मजदूरों को रिहा करना पड़ा. आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए एटक व अन्य यूनियनों के साथ सयुक्त मंच बना लिया गया है. हाल ही में सीटू का प्रभाव अहमदाबाद के 35 से भी ज्यादा मिलों में फैल गया है.

वटवा औद्योगिक क्षेत्र में इंजीनियरिंग उद्योग में विकास भी उसी तरह काबिलेतारीफ है. प्रबंधकों को एक संतोषजनक समझौता करने के लिए मजबूर करने के बाद आर. एम. इंजीनियरिंग वर्क्स में सीटू की सदस्यता एक हजार तक पहुंच गयी है.

सोराष्ट्र पेंट्स में कीमत वृद्धि का सामना करने के लिए मजदूरों ने पिछले समझोते के खत्म होने से पहले ही प्रबंधकों से पर्याप्त आर्थिक सुविधाएं प्राप्त कर ली हैं.

एवरेस्ट केमिकल्ज में, भारी आंदोलन ने प्रबंधकों को उन सभी 13 अगुवा कामगारों को, जिन्हें सेवामुक्त कर दिया गया था फिर से काम पर लेने के लिए मजबूर कर दिया.

ब्राईटो मेट में प्रबंधकों को पुलिस के साथ सांठगांठ से मान्यता प्राप्त सीटू यूनियन को तोड़ने के लिए बर्बर हमलों के खिलाफ मजदूर संघर्ष तेजी पकड़ रहा है. दो महिला कामगारों सहित आठ अगुवा मजदूरों को चार्जशीट दी गयी है और गिरफ्तार किया गया है.

छापाखाना मजदूरों के बीच जनरल प्रैस कामगार यूनियन धीरे धीरे संघर्ष को आगे बढ़ा रही है. नवजीवन प्रैस, अजय प्रिंटिंग प्रैस और वादीलाल एन्ड कंपनी प्रैस में सीटू यूनियनों ने दृढ़ संघर्ष के माध्यम से प्रबन्धकों को उन्हें मान्यता देने व मजदूरों की आर्थिक मांगों को मानने के लिए मजबूर कर दिया. स्टोरमेक इंडिया लिमिटेड में भी सीटू के नेतृत्व में संघर्षों ने मजदूरों के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त की हैं.

फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ

सीटू के बढ़ते प्रभाव से भयभीत होकर अहमदाबाद डेरी के प्रबंधकों ने फूटपरस्त ताकतों की मजदूरों में सांप्रदायिक फिसाद खड़ा करने में मदद की. लेकिन सीटू के नेतृत्व में मजदूरों ने प्रबंधकों के इरादे नाकाम कर दिए और एकजुट संघर्ष से उनकी नापाक साजिशों की कब्र खोद दी. इस यूनियन का प्रबंधकों द्वारा स्थापित सांप्रदायिक नेता नौकरी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर हुआ और भाग गया.

म्यूनिसिपल कार्पोरेशन

सीटू की सही नीतियों व मजदूरों के निस्वार्थ काम से अहमदाबाद म्यूनिसिपल कार्पोरेशन में भारी संख्या में मजदूर प्रभावित हुए हैं और उन्होंने अपने अवसरवादी नेता को छोड़ दिया तथा सीटू में खुल्मखुल्ला शामिल हो गए. इस अलग-थलग पड़े सीटू नेता का चरित्र उस समय सामने आया जब वह कांग्रेस (आई) में शामिल हो गया. सीटू ने यूनियन का सफल हड़ताल करने में नेतृत्व किया और म्यूनिसिपल कमिश्नर व उनके डिप्टी को मजदूरों की मांगें स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया.

एस्मा के खिलाफ सभी यूनियनों का सम्मेलन

सीटू के नेतृत्व में लगातार संघर्षों ने कामकाजी जनता के सभी हिस्सों को अपने जनवादी व हड़ताल के बुनियादी ट्रेड यूनियन अधिकारों की रक्षा करने और अधिनायकवादी हमलों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए एकजुट कर दिया है. घृणित अनिवार्य सेवा कानून (एस्मा) के खिलाफ प्रतिरोध करने के लिए 21 अक्तूबर को सभी यूनियनों का एक सम्मेलन होगा. कीमतवृद्धि व सरकार की श्रमविरोधी नीतियों के खिलाफ बंबई सम्मेलन द्वारा तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार 3 नवंबर को अखिल भारतीय प्रतिरोध व मांग दिवस मनाने तथा 23 नवंबर को संसद पर मार्च में भाग लेने के लिए तैयारियां हो रही हैं □

महिलाओं का विश्व सम्मेलन

महिलाओं का विश्व सम्मेलन प्राग, चैकोस्लोवाकिया, में 8 से 15 अक्तूबर तक आयोजित किया गया. जिन मुख्य विषयों पर विचार किया गया वे हैं : महिलाएं व कार्य, ग्रामीण महिलाओं सहित, महिलाओं व शांति; महिलाओं का परिवार व समाज में असमान स्तर; राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महिलाओं के आंदोलन का तालमेल, आदि. भारत के विभिन्न संगठनों से 20 महिला प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया. आल इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटी आफ वर्किंग वूमैन की सचिव विमला रणदिवे ने सीटू की ओर से सम्मेलन में भाग लिया. □

अखिल भारतीय इस्पात मजदूर सम्मेलन अब 8-10 जनवरी 1982 को

कलकत्ता में 1 व 2 अक्तूबर को संपन्न आल इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटी आफ स्टील वर्कर्स यूनियंज की बैठक ने अखिल भारतीय इस्पात मजदूर सम्मेलन को कुछ कारणवश 8-10 जनवरी 1982 तक के लिए स्थागित करने का फैसला लिया. पहले कमेटी ने इसे 6-8 नवंबर को आयोजित करना तय किया था. सम्मेलन के स्थान में कोई परिवर्तन नही किया गया है और यह दुर्गापुर ही रहेगा.

सभी यूनियनों द्वारा मांग पत्र पेश किए जाने की बैठक ने समीक्षा की और इस्पात मजदूरों में मांग पत्र को जनप्रिय बनाने के लिए फौरी कदम उठाने का फैसला किया. इसने इस्पात मजदूरों में हस्ताक्षर अभियान शुरू करने का भी फैसला लिया ताकि ज्यादा से ज्यादा मजदूरों के समर्थन को प्राप्त किया जा सके. दिसंबर के अंत तक मजदूरों द्वारा हस्ताक्षर किए गए मांग पत्र को प्रबंधकों को पेश कर दिया जाएगा.

दुर्गापुर में रोबिनसेन की अध्यक्षता में पहले ही एक स्वागत समिति बना दी गयी है जो सम्मेलन की तैयारियां करेगी. समिति का पता है : 36/49, हर्षवर्धन रोड, दुर्गापुर-4. चंदा इकट्ठा करने का अभियान शुरू कर दिया गया है और स्वागत समिति पर्याप्त चंदा जुटाने की आशा करती है.

कोआर्डिनेशन कमेटी ने सम्मेलन के समक्ष मुद्दों को जनप्रिय करने के लिए स्थानीय अभियान शुरू करने का फसला लिया है. पोस्टर लगाने, पर्चे बांटने व चंदा इकट्ठा करने का कार्यक्रम भी तैयार किया गया.

बैठक ने टिस्को जमशेदपुर के प्रबंधकों द्वारा के. के. त्रिपाठी, नंदजी पांडे और अन्यों को 10,000 ठेका मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व करने के कारण बर्खास्त कर देने की निंदा की. इसने 24 अक्तूबर को सभी इस्पात प्लांटों पर गेट मीटिंगें आयोजित करने और उनकी नौकरी की बहाली की मांग करते हुए प्रस्तावों को पारित करने का फैसला लिया. इसने इस्पात प्रबंधकों द्वारा विक्टिमाइजेशन के दूसरे कदमों को वापस लेने की भी मांग की.

बैठक ने 3 नवंबर को एकजुट होकर सभी इस्पात नगरों में मनाने और 23 नवंबर को संसद के लिए संयुक्त मार्च में अच्छी भागीदारी के लिए तैयारियां करने का फैसला किया.

सम्मेलन में पेश की जाने वाली रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए कोआर्डिनेशन कमेटी की अगली बैठक दुर्गापुर में 14-15 अक्तूबर को होगी. इसमें प्रस्तावित फेडरेशन के संविधान का मसविदा भी, सम्मेलन में अपनाए जाने के लिए पेश करने के लिए तैयार किया जाएगा.

बामापद मुखर्जी ने बैठक की अध्यक्षता की और सीटू केंद्र से एम. के पंधे ने इसमें भाग लिया. □

भेल में बोनस के सवाल का आंशिक हल

नयी दिल्ली में 5 व 6 अक्तूबर को संपन्न भेल संयुक्त कमेटी की बैठक में 1980 साल के लिए केवल हरद्वार, त्रिची व हैदराबाद के प्लांटों के लिए बोनस तय हो गया है. समझौते के तहत 20 प्रतिशत बोनस तय हुआ है हालांकि उपलब्ध सरपलस को तय करने का मुद्दा हल करना अभी बाकी है. प्रबंधकों ने भोपाल के लिए 16.5 प्रतिशत बोनस का प्रस्ताव रखा लेकिन मजदूरों के दल ने 20 प्रतिशत की मांग की. सी एफ एफ पी (हरद्वार) और झांसी के लिए 8.33 प्रतिशत व साथ ही पिछले साल की तरह 160 से 210 रुपये देने का प्रस्ताव प्रबंधकों ने रखा. इन दोनों प्लांटों में भी मजदूरों के दल ने 20 प्रतिशत की मांग की. सीटू, एटक, बीएमएस व एचएमएस के प्रतिनिधियों की एक बैठक में यह तय किया गया था कि प्रबंधकों के दृष्टिकोण के खिलाफ एकजुट प्रतिरोध किया जाए और 20 प्रतिशत बोनस की मांग पर जोर दिया जाए.

शुरू में ही सीटू के प्रतिनिधियों ने प्रबंधकों को पिछले समझौते म तय नही किए गए दूसरे मुद्दों पर समझौता करने में देर करने की नीति की आलोचना की. प्रबंधकों ने पिछले चार महीनों से संयुक्त बैठक नहीं बुलाई. इसकी भी कई प्रतिनिधियों ने आलोचना की. प्रबंधकों ने 6 नवंबर को एक बैठक बुलाना स्वीकार किया और इसमें भेल मजदूरों के बाकी मुद्दों पर विचार किया जाएगा. अनेक प्रतिनिधियों ने गुप्त मतदान द्वारा नए चुनावों का सवाल उठाया लेकिन इंटक के प्रतिनिधियों ने चैक-आफ प्रणाली के लिए जोर दिया. यह फैसला लिया गया कि इस सवाल पर आगामी बैठक में विचार किया जाएगा.

बैठक में सीटू का प्रतिनिधित्व एम. के. पंधे व एन. वी. भास्कर राव ने किया. □

'दवा उद्योग व भारतीय जनता' पर गोष्ठी

'दवा उद्योग व भारतीय जनता' पर एक गोष्ठी 7 व 8 नवंबर को आल इंडिया इंस्टीच्यूट आफ मैडिकल साइंसेज, नयी दिल्ली में आयोजित की जाएगी. यह गोष्ठी छः संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है. संगठनों के नाम हैं: फेडरेशन आफ मैडिकल रिप्रेजेंटेटिव्ज एसोसिएशंज आफ इडिया (एफ एम आर ए आई), दिल्ली साइंस फोरम, सोसाइटी आफ यंग साइंटिस्ट्स, फोरम फार साइंस, टैक्नोलोजी एंड सोसाइटी, एसोसिएशन आफ साइंटिफिक वर्कर्स आफ इंडिया और आल इंडिया फेडरेशन आफ जूनियर डाक्टर्स एसोसिएशंज.

श्री पी. एन. हक्सर और डा० (श्रीमती) इमराना कदीर गोष्ठी के क्रमशः अध्यक्ष व संयोजक हैं. भारी संख्या में देश के प्रसिद्ध डाक्टर, वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री विभिन्न केंद्रीय ट्रड यूनियनों के प्रतिनिधियों सहित गोष्ठी में भाग लगे. □

साम्राज्यवाद को शिकस्त दो

[पृष्ठ दो से आगे]

विश्व और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग आंदोलन के लिए इस नाजुक हालत में, साम्राज्यवादी खेमे को बेनकाब करने में जनवादी चीन के दृष्टिकोण जिससे साम्राज्यवादी साजिशों को मदद मिलती है से अड़चन पैदा होती है.

पूंजीवादी दुनिया की तुलना में सोवियत संघ और समाजवादी देशों की धीरे-धीरे बेहद प्रगति हुई है. बेरोजगारी शाप उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर अब असर नही करता.काम के अधिकार की गारंटी है. कीमतें स्थिर हैं. जीवनयापन का स्तर लगातार बढ़ रहा है. यह आर्थिक प्रगति और भी तेज होती यदि समाजवादी देशों को अमरीकी साम्राज्यवादियों की हमलावर तैयारियों का मुकाबला करने के लिए डिफेंस पर भारी धन खर्च करने के लिए मजबूर न किया जाता.

यह माफ न कर सकने वाली गलती होती यदि तनाव शैथिल्य के जारी रहने पर विश्वास करके सोवियत संघ व समाजवादी देश मिलिटरी तैयारी के काम को नजरअंदाज कर देते. आज सोवियत संघ की सभी घटनाओं का सामना करने की ताकत, इसका आश्वासन कि अमरीका को मिलिटरी प्रभुता स्थापित करने नही दी जाएगी एक स्थायी गारंटी है कि विश्व-शांति को दंडमुक्ति के साथ भंग नही होने दिया जाएगा.

सोवियत संघ आर्थिक निर्माण में न केवल सफलताओं के बाद सफलताएं हासिल कर रहा है और अपनी जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठा रहा है, बल्कि यह विश्वशांति की भी रक्षा कर रहा है तथा अनेक देशों की अपनी स्वतंत्रता बचाए रखने में मदद कर रहा है. यह अमरीकी प्रभुता के रास्ते में खड़ा है. इसकी अफगानिस्तान व अंगोला को सहायता से साम्राज्यवादी पहले ही आग बबूले हैं. इस साल 7 नवंबर को मजदूर वर्ग को दृढ़ता के साथ यह घोषणा करनी है कि यह सोवियत संघ व समाजवादी दुनिया के खिलाफ सभी हमलों को नाकाम करेगा, शांति की रक्षा करेगा और दुनिया को न्यूक्लीयर युद्ध के नरसंहार से बचाएगा. साम्राज्यवादी युद्ध के खिलाफ संघर्ष से ही 1917 की क्रांति पैदा हुई थी, इसने नाजी साम्राज्यवादी हमले का सामना किया और उसे शिकस्त दी और फिर विश्व शांति को अपना पूरा समर्थन दिया. इस बार विश्व मजदूरवर्ग और दुनिया की जनता की सहायता से जंगबाजों को यह तंग शिकंजे में डालने की स्थिति में है. विश्व शांति के लिए अपने संघर्ष की सफलता की गारंटी के लिए देश का मजदूर वर्ग तथा प्रगतिवादी ताकतें एकजुट हों. □

पश्चिम बंगाल समाचार

सफल बोनस संघर्ष

पश्चिम बंगाल में मजदूर वर्ग एकजुट संघर्षों के माध्यम से अनेक उद्योग में अपनी बोनस की मांग को पूरा कराने में विजयी रहा है. इंदिरा सरकार के अधिनायकवादी कदमों और उसके श्रमविरोधी कानूनों से प्रोत्साहित होकर विभिन्न उद्योगों के मालिकान ने बोनस की मांग के प्रति यहां तक कि कानूनी न्यूनतम के प्रति भी, कड़ा दृष्टिकोण अपना लिया था.

राज्य श्रम मंत्री द्वारा स्टेट लेबर एडवाइजरी बोर्ड की बैठक आयोजित किये जाने पर मालिकान के प्रतिनिधियों ने आर्थिक हानि का बहाना लिया हालांकि उनके मुनाफे पिछले साल की तुलना में ज्यादा थे. जूट मिल मालिकान ने न्यूनतम बोनस भी देने से इंकार कर दिया.

लेकिन कलकत्ता, हावड़ा, हुगली, 24-परगना, असनसोल, दुर्गापुर आदि जैसे सभी औद्योगिक क्षेत्रों में एकजुट संघर्षों के माध्यम से मजदूरों ने इंजीनियरिंग, रबड़, टैनरी, रसायन पाटरी व अन्य उद्योगों में 12 से 20 प्रतिशत तक बोनस हासिल किया. बीड़ी, तबाकू, तेलमिलों व वोल्फरैम फैक्ट्रियों के मजदूरों को भी इसी तरह कामयाबी मिली. कलकत्ता व अन्य जिलों में निजी ट्रांसपोर्ट मजदूरों को भी संघर्षों द्वारा इस साल अधिक बोनस मिला. हिंदुस्तान मोटर्स वर्कर्स यूनियन (सीटू) के नेतृत्व में हिंदुस्तान मोटर्स के 16 हजार मजदूरों को एक लंबे संघर्ष के बाद 20 प्रतिशत बोनस प्राप्त हुआ.

सबसे अड़ियल व अक्खड़ मालिकान आई जे एम ए के तहत जूट सामंत हैं जिन्होंने श्रम मंत्री की सिफारिशों को भी अस्वीकृत कर दिया है. □

रीगन-अर्थशास्त्र के खिलाफ 'अमरीका की आवाज'

रीगन की आर्थिक नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध करने के लिए ए एफ एल--- सी आई ओ ने 19 सितंबर को राजधानी वाशिंगटन में 5 लाख मजदूरों का एक भारी मोर्चा निकाला जो अमरीका के इतिहास मे सबसे बड़ा था. मजदूरों द्वारा "रीगन गरीबों को लूटता है, अमीरों को खिलाता है", "रीगन के अर्थशास्त्र का शिकार करो" नारे लगाए गए. रीगन अर्थशास्त्र के आंकडे हैं: इस साल की दूसरी तिमाही में अमरीका का जी एन पी 2.4 प्रतिशत गिरा; अगस्त में एक करोड़ बेरोजगार; गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले अमरीकियों की 1980 में संख्या तीन करोड़ थी; केवल 1980 में ही मजदूरों का वास्तविक वेतन 5.5 प्रतिशत गिरा.

आवेशपूर्ण युद्ध की तैयारियों के लिए, 1982 के लिए रीगन का डिफेंस बिल 224 अरब डालर हैं जो अमरीका के इतिहास में सबसे महंगा मिलिटरी कदम है और इसे सभी सामाजिक कार्यक्रमों को त्याग कर या उनमें कमी करके उठाया गया है. □

सीटू मजदूर

एक प्रति की कीमत 50 पैसे
सालाना चंदा छः रुपये
कम से कम पांच प्रतियों की एजेंसी लिखें :

सीटू कार्यालय
6, तालकटोरा रोड,
नई दिल्ली 110001

जे. के. ग्रुप के मजदूरों का सम्मेलन

जे. के. ग्रुप में संघर्ष अखिल भारतीय शक्ल लेने वाला है. समूचे भारत के जे. के. ग्रुप व रेयान मजदूर, क्लोजर की धमकी के खिलाफ 7 व 8 नवंबर को कानपुर में एक सम्मेलन में मिलेंगे.

पिछले दो सालों से जे. के. रेयान कानपुर के मजदूर प्रबंधकों के घिनौने हमलों का बहादुरी से प्रतिरोध कर रहे थे. मान्यताप्राप्त सीटू यूनियन को नजरअंदाज करते हुए प्रबंधकों ने इंटक की एक यूनियन बनवाई और मजदूरों पर भारी दमन ढाना शुरू कर दिया. पिछले पांच सालों में भारी संख्या में मजदूरों की छटनी की जा चुकी है और नेतृत्व के एक हिस्से को बर्खास्त कर दिया गया है. प्रबंधकों के साथ सीधे-सीधे सांठ-गांठ करके पुलिस ने कई मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया.

इन हालात में सीटू ने अपनी जनरल काउंसिल की पिछली बैठक में जे. के. मजदूरों के संघर्ष पर विचार किया तथा जे. के. ग्रुप में यूनियनों की एक बैठक 10 अक्तूबर को कानपुर में आयोजित की. बैठक ने जेके ग्रुप व रेयान मजदूरों का समूचे देश में संघर्ष फैलाने के कदम उठाने तथा कानपुर के संघर्षरत मजदूरों के साथ एकजुटता का इजहार करने के लिए एक सम्मेलन बुलाने का फैसला लिया था. □

कोटा जे के ग्रुप मजदूरों का विजयी बोनस संघर्ष

सीटू के नेतृत्व में मजदूरों के दृढ़ एकजुट संघर्ष ने कोटा में जे के ग्रुप के सभी उद्योगों को उनको अधिक बोनस देने के लिए मजबूर कर दिया. जे के सिंथेटिक्स, जे के स्टैपल व टूल्स तथा जे के टायर कार्ड को बीस प्रतिशत बोनस के अलावा पर्याप्त एक्स-ग्रेशिया की अदायगी भी स्वीकार करनी पड़ी. जिला कमेटी सचिव पी. एन. ढांढा ने इस शानदार जीत पर मजदूरों को बधाई दी है. □

कोल इंडिया के प्रबंधक द्विपक्षीय मंच से भाग रहे हैं

हालांकि पिछले वेतन समझौते से उत्पन्न कई समस्याओं का अभी समाधान करना बाकी है प्रबंधको ने इस बहाने से कि इंटक ने अपना प्रतिनिधि वापिस बुला लिया है कोयला उद्योग के लिए संयुक्त द्विपक्षीय कमेटी (जे बी सी सी आई) को कार्यरूप में बंद करने का फैसला ले लिया है.

प्रबंधकों ने 29 व 30 सितंबर की स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी की बैठक भी सदस्यों को उपयुक्त नोटिस दिए बिना रद्द कर दी थी.इ सी तरह 23 अक्तूबर को कोयला उत्पादन पर होने वाली द्विपक्षीय बैठक को भी प्रबंधकों ने एकतरफा तौर पर रद्द कर दिया.

सी आई एल मुख्यालय में 3 सितंबर को संपन्न जे बी सी सी आई की बैठक इंटक के निकल जाने पर विचार विमर्श हुआ था. इसमें इस पर सहमति थी कि हालांकि द्विपक्षीय मंच में इंटक के प्रतिनिधि को वापस बुलाने की कोशिशें जारी रहें लेकिन कमेटी का कार्य नहीं रुकना चाहिए क्योंकि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी फैसला लिया जाना है.

सीटू, एटक, एच एम एस व बी एम एस के प्रतिनिधियों ने सी आई एल के प्रबंधकों को इस रवैये के खिलाफ प्रतिरोध तथा जे बी सी सी आई की तुरंत बहाली की मांग करते हुए एक ही तरह के पत्र लिखे हैं. उन्होंने सी आई एल के प्रबंधकों को चेतावनी दी कि यदि मंच को तुरंत बहाल नहीं किया गया तो वे अनिर्णित मुद्दों पर कोयला मजदूरों का देशव्यापी आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होंग. □

कानपुर के जूट मजदूरों की 'अंदर रहो' अनिश्चितकालीन हड़ताल

कानपुर के जूट मजदूरों ने जे. के. जूट मिल्स कंपनी को 17 नवंबर से अनिश्चितकालीन 'अन्दर रहो' हड़ताल का नोटिस दे दिया है. सीटू, एटक, एच एम पी व बी एम एस की चार यूनियनों ने प्रबंधकों को एक 27-सूत्री मांग पत्र दिया था जिसमें एमर्जेंसी में निकाले गए मजदूरों की बहाली व अन्य मांगें शामिल थीं. यूनियनों की लबी व पूरी कोशिशों के बावजूद प्रबंधकों ने समझौतावार्ता से इंकार कर दिया. संघर्ष के संचालन के लिए यूनियनों ने संयुक्त संघर्ष समिति बनाई है. संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रबंधकों को यह भी सूचित कर दिया है कि यदि 'अंदर रहो' हड़ताल के लिए विकिटमाइजेशन किया गया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएगे □

बाटा मजदूरों की हड़ताल

बाटा शू कंपनी के 11 हजार मजदूरों व कर्मचारियों ने छटनी किए गए 6 मजदूरों की बहाली की मांग करते हुए 18 सितबर को आम हड़ताल की. फैक्टरी गेट पर आयोजित एक विशाल रैली में मजदूरों ने सघर्ष को तब तक जारी रखने का फैसला किया जब तक विक्टिमाइज मजदूरों को वापिस नही लिया जाता. □

आई एल ओ की गोष्ठियों में सीटू प्रतिनिधि

सीटू ने पश्चिम बंगाल से बिद्युत गांगुली व तरित तोपदार तथा तमिलनाडु से टी. नंदगोपाल व डी. जानकी रमन को आई एल ओ द्वारा प्लांट लेवल इंडस्ट्रियल रिलेशज पर क्रमशः कलकत्ता में 2 से 5 नवंबर तथा मद्रास में 9 से 12 नवंबर को आयोजित गोष्ठियों में भाग लेने के लिए नामजद किया है. □

सरकार की श्रम नीतियां दोषी : सीटू

केंद्रीय श्रम मंत्री श्री नारायण दत्त तिवाड़ी 12-14 अक्तूबर को नई दिल्ली में सीटू व अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों से देश में औद्योगिक संबंध स्थिति पर बातचीत करने के लिए अलग अलग मिले. सरकारी पक्ष ने औद्योगिक कमेटियों व नेशनल अपेक्स बाडी के पुनर्स्थापन तथा भारतीय श्रम सम्मेलन के आयोजन जैसे कई सवाल भी उठाए.

सीटू प्रतिनिधि पी. राममूर्ति व एम. के. पंधे ने जो 12 अक्तूबर को उनसे मिले केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से सलाह मशविरे की नीति को त्यागने के लिए भारत सरकार की कड़ी निंदा की. बंबई सम्मेलन के बाद भी सरकार ने सम्मेलन में उठाए गए मुद्दों पर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से बातचीत शुरू नहीं की. सरकार ने न केवल मजदूर वर्ग को काफी प्रभावित करने वाले मुद्दों पर, जैसे महंगाई के आंकड़ों की 1981 सीरीज को लागू करना, तथा प्रोविडेंट फंड रिव्यू कमेटी की सिफारिशों आदि पर परामर्श पद्धति को मात्र औपचारिकता बनाते हुए एकतरफा फैसले लिए हैं बल्कि मजदूर वर्ग के बढ़ते संघर्षों का दमन करने लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और अनिवार्य सेवा कानून जैसे कठोर कानून भी लागू किए हैं. उन्होने कहा कि इस समय सलाहमशविरे का मतलब है तलवार की धार पर विचार विमर्श.

सभी ट्रेड यूनियनों, खासतौर से सीटू, के खिलाफ भेदभाव के लिए तथा विभिन्न कमेटियों में नामांकन के लिए पिट्ठू इंटक के प्रति नंगा पक्षपात करने के लिए सीटू ने सरकार को दोषी ठहराया. कई उद्यमों में सरकार के कहने पर प्रबंधकों ने जाली पिट्ठू इंटक यूनियन के साथ मान्यता प्राप्त यूनियनों को नजरअंदाज करते हुए समझौते किए जैसा कि जे के रेयान कानपुर व अन्य जगहों पर हुआ.

सीटू ने संघर्षों पर बर्बर दमन की निंदा की और ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं व नेताओं पर कांग्रेस (आई) के गुंडों के बढते हमलों पर चिंता व्यक्त की. दस घंटे ड्यूटी के अपने समझौते से मुकर जाने व बदले की भावना से लोकोकर्मियों पर दमन ढाने, रेलवे में बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं के बढ़ने, सभी श्रम सुरक्षा नियमों के धराशायी होने, असम चाय बगान मजदूरों पर बर्बर हमलों, हरियाणा में पुलिस दमन, सीटू नेताओं जैसे उड़िसा में अजेय राउत व तमिलनाडु में सी गोविंदराजन पर कातिलाना हमलों तथा मोदीनगर में एच एम एस के नेता की हत्या की उदाहरणें सीटू नेताओं ने दीं.

सीटू नेताओं ने कहा कि भारत सरकार की इन नीतियों की वजह से औद्योगिक विवादों के तुरंत फैसलों की बजाए तनाव और बढ़ रहा है.

ऊंची कीमतों, वास्तविक वेतनों में गिरावट, ग्रामीण जनता की कंगाली तथा बड़े औद्योगिक घरानों व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बेतहाशा मुनाफों के लिए सीटू ने सरकार की आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि जब तक इन नीतियों को बदला नहीं जाता है मजदूरों में असंतोष बढ़ता रहेगा.

सरकार द्वारा तय किए गए जांच पड़ताल के नए तरीके को सीटू ने सुस्पष्टता से अस्वीकार कर दिया तथा विवादास्पद यूनियनों की ताकत के फसले के लिए गुप्त मतदान कराने पर पुनः जोर दिया. सरकार ने समूचे ट्रेड यूनियन आंदोलन की राय को नजरअंदाज करते हुए पिट्ठू इंटक को कार्यरूप में वीटो का अधिकार दे दिया है.

सीटू ने कहा कि केंद्रीय श्रम मंत्री का अस्तित्व बेमानी है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत कोई भी मंत्रालय श्रम मंत्रालय को कुछ समझता नही है जबकि निजी क्षेत्र में विवादों से राज्य सरकारें निबटती हैं. इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक विवादों पर कोई प्रभाव डालने में श्रम मंत्रालय नाकामयाब है.

रथ कमेटी की सिफारिशों तथा ट्रेड यूनियन संगठनों के नोट के अनुसार मूल्य सूचकांक को न सुधारने के भारत सरकार के एकतरफा फैसले की सीटू नेताओं ने आलोचना की.

उन्होंने जोर देकर कहा कि कंसीलेशन प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने का सरकार का कदम सामूहिक सौदेबाजी का वास्तविक विकल्प नहीं हो सकता. उन्होंने जबरन मध्यस्थता तथा सरकारी कर्मचारियों के मामले में मध्यस्थ के फैसले रद्द करने या उसमें संशोधन करने की सरकार की शक्ति का विरोध किया.

वे इससे सहमत हुए कि औद्योगिक कमेटियों की बहाली सहायक हो सकती है अगर इनकी बैठकें नियमित रूप से हों तथा ट्रेड यूनियनों को बैठकों की कार्यसूची तय करने का अधिकार हो. नेशनल अपेक्स बाडी को बहाल करने के प्रस्ताव की विस्तृत जानकारी सरकार ने अभी नहीं दी है. इसलिए इसके मिलने के बाद ही सीटू की पक्की राय जानी जा सकती है. भारतीय श्रम सम्मेलन आयोजित करने के सवाल पर उन्होंने सम्मेलन को दो बार मनमर्जी से स्थगित करने की निंदा की और बताया कि औद्योगिक संबंध स्थिति पर विचार करने के लिए 1977 से अब तक कोई भी त्रिपक्षीय बैठक नहीं हुई है.

औद्योगिक संबंध विधेयक को जिसे समूचे ट्रेड यूनियन आंदोलन ने रद्द कर दिया था, बहाल करने तथा इसे औद्योगिक विवाद कानून में संशोधनों के रूप में लाने की कोशिशों की सीटू ने कड़ी निंदा की. यह बताते हुए कि और देरी करने से औद्योगिक संबंध आगे बिगड़ेंगे ही, सीटू ने भारतीय श्रम सम्मेलन को शीघ्र ही आयोजित करने की मांग की. यह आशा व्यक्त की गई कि केंद्रीय श्रम मंत्री को दिए गए ज्ञापन में उठाए गए मुद्दों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी. □

सिप्लैक्स में संघर्ष जारी

भारी दमन व गुंडा हमलों का सामना करते हुए, भिलाई (म. प्र.) में सिप्लैक्स इंजीनियरिंग के मजदूर अपने संघर्ष को दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ा रहे हैं. मजदूर अप्रैल 1981 से हड़ताल पर हैं. पांच मजदूरों को गैरकानूनी तौर से नौकरी से निकालने पर यह हड़ताल शुरू हुई थी. शांतिमय ढंग से संघर्षरत मजदूरों को 21 अप्रैल को फैक्टरी क्षेत्र के अंदर पुलिस द्वारा पीटा गया. 12 मजदूरों को झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया. हड़ताली सिप्लैक्स मजदूरों के समर्थन में कई फैक्ट्रियों के मजदूरों ने एक दिन की हड़ताल की और डी एम को एक ज्ञापन दिया. सिप्लैक्स उद्योग के मजदूरों ने 23 अप्रैल से और सिप्लैक्स कास्टिंग के मजदूरों ने 3 मई से हड़ताल में भाग लिया.

मजदूरों की एक विशाल रैली एक मई को सिप्लैक्स इंजीनियरिंग के गेट पर संपन्न हुई. प्रबंधकों व इसके गुंडों से सांठगांठ करके पुलिस ने 4 मई को मजदूरों पर हमला किया तथा 44 को गिरफ्तार किया. प्रबंधकों के गुंडों ने 25 मई को यूनियन आफिस पर हमला किया तथा पुलिस ने 87 मजदूरों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने 4 जून को सीटू की मध्य प्रदेश राज्य कमेटी के उपाध्यक्ष पी. के. मोइत्रा को गिरफ्तार किया. वह अभी तक जेल में हैं.

हड़ताली मजदूरों के समर्थन में 20 सितंबर को सिप्लैक्स कास्टिंग के गेट पर एक रैली आयोजित की गई. रैली को अन्यों के अलावा हन्नन मोल्लाह, एम. पी. तथा मध्य प्रदेश डी वाई एफ आई के अध्यक्ष बादल सरोज ने संबोधित किया. रैली में छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ, राजहरा के मजदूरों ने हड़ताली मजदूरों के लिए 15 बोरी चावल दिए.

सीटू की मध्य प्रदेश राज्य कमेटी ने सभी सीटू यूनियनों का आह्वान किया है कि वे हड़ताली सिप्लैक्स मजदूरों के साथ एकजुटता का इजहार करें तथा उनके संघर्ष फंड के लिए अनुदान इकट्ठा करें. □

ए यू सी सी टी यू को शुभकामनाएं

एतिहासिक अक्तूबर क्रांति की 64वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोवियत संघ की आल यूनियन सेंट्रल काउंसिल आफ ट्रेड यूनियंस को सीटू हार्दिक बिरादराना शुभकामनाएं भेजती है.

गहराते आर्थिक संकट, जिसने पूंजीवादी दुनिया को उनकी प्रगति दर में गिरावट लाकर झकझोर दिया है, की तुलना में ए यू सी सी टू यू के नेतृत्व में सोवियत संघ के मजदूर वर्ग ने स्थिर प्रगति बनाए रखी जो कई क्षेत्रों में अमरीका को मात कर गई है तथा जनता को जीवनयापन के बेहतर स्तर की गारंटी दी है. अपने प्रयासों में ए यू सी सी टी यू की आगे सफलताओं की सीटू कामना करती है.

ए यू सी सी टी यू व सीटू के बीच बढ़ते दोस्ताना संबंधों तथा बेहतर समझ को नोट करके सीटू प्रसन्न है. सीटू के उपाध्यक्ष के. रमनी तथा सचिव एम. के पंधे की यात्रा से और ए यू सी सी टी यू के नेतृत्व के साथ स्वतंत्र व स्पष्ट विचार विनिमय से दोस्ताना संबंध और भी मजबूत हुए हैं, और सीटू को विश्वास है कि भविष्य में ये और भी मजबूत होंगे. □

बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों के खिलाफ सम्मेलन

यू.पी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ने 4 अक्तूबर को लखनऊ में दवा उद्योग में बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर एक सम्मेलन आयोजित किया. बैंक, एल आई सी, जी आई सी, रेलवे, सरकारी कर्मचारियों, डाक्टर, अध्यापकों व अन्य जन संगठनों के अनेक नुमाइंदों ने सम्मेलन में भाग लिया जिसका उद्घाटन फेडरेशन आफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशंस आफ इंडिया के महासचिव जे एस मजूमदार ने किया. सम्मेलन ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव अपनाया जिसमें दवा उद्योग में बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा भारतीय एकाधिकारियों का राष्ट्रीयकरण करने की मांग की गई. □

टी यू आई के सचिव सीटू कार्यालय आए

ट्रेड यूनियन इंटरनैशनल आफ आयल, केमिकल्स एंड अलाइड वर्कर्स (आइ सी पी एस) के सचिव पाल गार्गेल, जो आल इंडिया केमिकल्स एंड फार्मेस्यूटिकल एंप्लाईज फेडरेशन के निमंत्रण पर दवा उद्योग पर एक गोष्ठी में भाग लेने के लिए भारत भ्रमण पर हैं, 24 अक्तूबर को सीटू कार्यालय आए. ट्रेड यूनियन गतिविधियों के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए तथा सीटू के डब्ल्यू एफ टी यू व टी यू आई के साथ बिरादराना संबंधों को मजबूत करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने सीटू नेतृत्व से बातचीत की. □

संपादक मंडल

बी. टी. रणदिवे (अध्यक्ष)
पी. राममूर्ति मनोरंजन राय
नीरेन घोष सुधीन कुमार
एम. के. पंधे (संपादक)

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के लिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 (फोन : 384071) से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, सी 52-53 डी.डी.ए. शेडस्, ओखला, फेज-I, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित